माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की विभिन्न प्रभावी समस्याओं का विश्लेषण

(Analysis of Various Effective Problems of Teachers of Secondary Schools)

रविन्द्र कुमार कौशिक
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा एवं मनोविज्ञान संकाय,
मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) भारत।
डा0 मुनेन्द्र कुमार त्यागी
आचार्य, शिक्षा विभाग, शिक्षा एवं मनोविज्ञान संकाय,
मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) भारत।

शोधपत्र सार

प्रस्तुत शोध पत्र शोधार्थी द्वारा ''उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' विषय पर किये गये शोध अध्ययन के आँकड़ा विश्लेषण एवं परिणामों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं यथा– प्रशासनिक समस्याएँ, शैक्षिक समस्याएँ, भौतिक संसाधनों की समस्याएँ, वित्तीय समस्याएँ, व्यावसायिक समस्याएँ तथा अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं का ही विश्लेषण व उनके परिणामों का वर्णन किया गया है। शोध कार्य हेतु मेरठ तथा सहारनपुर मण्डल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि का प्रयोग कर कुल 300 सेवारत् अध्यापकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। इस हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित शोध–प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया तथा केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों तथा उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण कर शोध परिकल्पनाओं का सत्यापन का शोध उद्देश्यों की सफलतम प्राप्ति की गई। विश्लेषण के आधार पर यह परिणाम प्राप्त होता है कि राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्याएँ भिन्न–भिन्न हैं तथा तुलनात्मक रूप से समस्याओं का प्रतिशत; वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का अधिक है, जिन्होंने समस्याओं के विभिन्न क्षेत्रों– प्रशासनिक, शैक्षिक, भौतिक–संसाधन, वित्तीय, व्यावसायिक व अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं को अधिक प्रतिशत के रूप में माना है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्याएँ भिन्न–भिन्न हैं तथा तुलनात्मक रूप से समस्याओं में अन्तर है।

शोध का प्रमुख उद्देश्य –

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भिन्न–भिन्न समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना निम्नप्रकार है–

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रभावी समस्याएँ भिन्न–भिन्न होंगी।

आँकड़ा विश्लेषण तथा परिल्पना सत्यापन–

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी समस्याओं का विश्लेषण

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने छः प्रकार की समस्याएँ बतायी हैं; जैसे– प्रशासनिक, शैक्षिक, भौतिक–संसाधनों से सम्बन्धित, वित्तीय, व्यावसायिक एवं अनुशासन सम्बन्धी समस्याएँ। अतः प्रदत्तों के विश्लेषण की पुष्टि हेतु सम्पूर्ण समस्याओं को राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के क्रम में रखकर, उनकी प्रतिशतता–क्रम में विवेचना की गयी है।

यहाँ राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रशासनिक समस्याओं से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रतिशत को तालिका संख्या–1 में अग्रवत् दर्शाया गया है–

तालिका संख्या– 1

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रशासनिक समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अध्यापकों पर प्रबंध समितियों का अनापेक्षित दबाव।	60	75.0	200	90.90	260	86.66
2	विद्यालयों की स्थायी सम्बद्धता/मान्यता की समस्या।	50	62.5	210	95.45	260	86.66
3	प्रशासनिक कार्यों में प्रबन्धतंत्र की अनापेक्षित दखलंदाजी।	48	60.0	212	96.36	260	86.66
4	प्रशासनिक नीतियों में बार–बार परिवर्तन से शिक्षण–कार्यों में बाधा उत्पन्न होना।	50	62.5	210	95.45	260	86.66
5	विद्यालय–परिसर में आवास की सुविधा न होने के कारण असंतोष।	60	75.0	200	90.90	260	86.66
6	विद्यालयों में कम प्रवक्ताओं की नियुक्ति से ही कार्य चलाना।	10	12.5	210	95.45	220	73.33
7	प्रबंधतंत्र द्वारा अध्यापकों को सरकार द्वारा निर्धारित सी.एल./ई.एल. देने में अवरोध उत्पन्न करना।	04	05.0	216	98.18	220	73.33

8	विद्यालयों में समुचित कर्मचारियों के अभाव में अध्यापकों से लिपिकीय कार्य करवाना।	20	25.0	206	93.63	226	75.33
9	प्रशासनिक उत्तरदायित्व में शैक्षिक संवेदना की अवहेलना।	20	25.0	200	90.90	220	73.33
10	विद्यालयों में धनार्जन की प्रवृत्ति के कारण गुणात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का तिरोहण।	04	05.0	210	95.45	214	71.33
11	अध्यापकों की सेवा–शर्तों में अस्थिरता के कारण आर्थिक एवं मानसिक तनाव की समस्या।	10	12.5	214	97.27	224	74.66
12	प्रशासनिक अस्थिरता के चलते शैक्षिक–गतिरोध की समस्या।	20	25.0	200	90.90	220	73.33
13	शैक्षिक–उन्नयन हेतु आयोजित कार्यशालाओं में अध्यापकों की सहभागिता में गतिरोध पैदा करना।	10	12.5	212	96.36	222	74.00
	माध्य प्रतिशत		35.19		94.40		78.61

तालिका संख्या–1 से स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में से समस्या–1 पर 75 प्रतिशत, समस्या–2 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–3 पर 60 प्रतिशत, समस्या–4 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–5 पर 75 प्रतिशत, समस्या–6 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–7 पर 5 प्रतिशत, समस्या–8 पर 25 प्रतिशत, समस्या–9 पर 25 प्रतिशत, समस्या–10 पर 5 प्रतिशत, समस्या–11 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–12 पर 25 प्रतिशत तथा समस्या–13 पर 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में से समस्या–1 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–2 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–3 पर 96.36 प्रतिशत, समस्या–4 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–5 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–6 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–7 पर 98.18 प्रतिशत, समस्या–8 पर 93.63 प्रतिशत, समस्या–9 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–10 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–11 पर 97.27 प्रतिशत, समस्या–12 पर 90.90 प्रतिशत तथा समस्या–13 पर 96.36 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः औसत रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याएँ अधिक हैं। शोधकर्ता ने प्रत्येक प्रशासनिक समस्या की प्रतिशत के आधार पर विवेचना की है। यह इस प्रकार हैं–

समस्या–1 अध्यापकों पर प्रबन्ध–समितियों का अनपेक्षित दबाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने 75 प्रतिशत एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है।

समस्या–2 विद्यालयों की स्थायी सम्बद्धता/मान्यता की समस्या।

उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट होता है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–3 प्रशासनिक कार्यो में प्रबन्धतंत्र की अनापेक्षित दखलंदाजी।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 60 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 96.36 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–4 प्रशासनिक नीतियों में बार–बार परिवर्तन से शिक्षण–कार्यों में बाधा उत्पन्न होना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–5 विद्यालय–परिसरों में आवास की सुविधा न होने के कारण असंतोष।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–6 विद्यालयों में कम प्रवक्ताओं की नियुक्ति से ही कार्य चलाना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है।

समस्या–7 प्रबन्ध–तंत्र द्वारा अध्यापकों को सरकार द्वारा निर्धारित सी.एल./ई.एल. आदि देने में अवरोध उत्पन्न करना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 5 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 98.18 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है।

समस्या–8 विद्यालयों में समुचित कर्मचारियों के अभाव में अध्यापकों से लिपिकीय कार्य लेना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 93.63 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है। तथा यहाँ प्रवक्ताओं को शिक्षण–कार्य के अतिरिक्त लिपिकीय कार्य भी करने पड़ते हैं।

समस्या–9 प्रशासनिक उत्तरदायित्व में शैक्षिक–संवेदना की अवहेलना।

उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–10 विद्यालयों में धर्नाजन की प्रवृत्ति के कारण गुणात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का तिरोहण।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 5 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रभावी समस्या है।

समस्या–11 अध्यापकों की सेवा–शर्तो में अस्थिरता के कारण आर्थिक एवं मानसिक तनाव की समस्या।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 97.27 प्रतिशत अध्यापकों ने इस समस्या को सही बताया है। अतः स्पष्ट होता है कि वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा–शर्तें अधिक अस्थिर होती हैं।

समस्या–12 प्रशासनिक अस्थिरता के चलते शैक्षिक–गतिरोध की समस्या।

उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–13 शैक्षिक–उन्नयन हेतु आयोजित कार्यशालाओं में अध्यापकों की सहभागिता में गतिरोध पैदा करना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 96.36 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी

समस्या है।

राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं के आँकड़ों के प्रतिशत को तालिका संख्या–2 द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका संख्या–2

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	विद्यालयों में शैक्षिक–अनुसंधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।	60	75.0	220	100	280	93.33
2	अध्यापकों के लिए ज्ञान को ताजा करने वाले पाठयक्रम में सहभागिता हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।	50	62.5	220	100	270	90.00
3	समृद्ध पुस्तकालयों के अभाव में नवीन शैक्षिक जानकारियाँ उपलब्ध न होने की समस्या।	60	75.0	220	100	280	93.33
4	अध्यापको के लिए शैक्षिक–भ्रमण की सुविधा न मिलने की समस्या।	50	62.5	200	90.90	250	83.33
5	समय–समय पर शैक्षिक–संगोष्ठी का आयोजन न होने के कारण शैक्षिक–नवाचारों से अवगत न होने की समस्या।	50	62.50	210	95.45	260	86.66
6	अध्यापकों के लिए शैक्षिक–अद्यतन सामग्री का अभाव।	56	70.00	204	92.72	260	86.66
7	विद्यालयों में गुणत्मक सुधार की दृष्टि से विषयानुगत प्रवक्ताओं की नियुक्ति का अभाव।	70	87.50	200	90.90	270	90.00
8	विद्यालयों में शैक्षिक–नेतृत्व एवं शैक्षिक–पर्यावरण की कमी।	40	50.00	180	81.81	220	73.33
9	वर्तमान पाठयक्रम का आधुनिक जीवन के उद्देश्यों के अनुकूल न होना।	60	75.00	196	89.09	256	85.33
10	शैक्षिक स्वतंत्रता के अभाव में स्तरानुकूल–शिक्षण में कठिनाई।	58	72.5	204	92.72	262	87.33
11	पुस्तकालयों में स्तरीय–सुविधा का अभाव।	36	45.00	210	95.45	246	82.00
	माध्य प्रतिशत		67.04		93.55		86.48

तालिका संख्या–2 को देखने से ज्ञात होता है कि समस्या–1 पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने 75 प्रतिशत, समस्या–2 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–3 पर 75 प्रतिशत, समस्या–4 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–5 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–6 पर 70 प्रतिशत, समस्या–7 पर 87. 50 प्रतिशत, समस्या–8 पर 50 प्रतिशत, समस्या–9 पर 75 प्रतिशत, समस्या–10 पर 72.50 प्रतिशत तथा समस्या–11 पर 45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में समस्या–1 पर 100 प्रतिशत, समस्या–2 पर 100 प्रतिशत, समस्या–3 पर 100 प्रतिशत, समस्या–4 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–5 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–6 पर 92.72 प्रतिशत, समस्या–7 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–8 पर 81.81 प्रतिशत, समस्या–9 पर 89.09 प्रतिशत, समस्या–10 पर 92.72 प्रतिशत तथा समस्या–11 पर 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शैक्षिक–समस्याएँ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अपेक्षा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में अधिक प्रभावी है। शोधकर्ता ने प्रत्येक शैक्षिक–समस्या की प्रतिशत के आधार पर विवेचना की है। यह निम्न प्रकार है–

समस्या–1 विद्यालयों में शैक्षिक–अनुसंधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रदर्शित की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक गंभीर समस्या है, जहाँ शैक्षिक–अनुसंधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

समस्या–2 अध्यापकों के लिए ज्ञान को ताजा करने वाले पाठ्यक्रमों में सहभागिता हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की एक प्रभावी समस्या है। उनको इन पाठ्यक्रमों में भेजने हेतु सवेतन अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।

समस्या–3 समृद्ध पुस्तकालयों के अभाव में नवीन शैक्षिक जानकारियाँ उपलब्ध न होने की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या प्रतीत होती है, क्योंकि इन संस्थाओं में काम–चलाऊ पुस्तकालयों से ही काम चलाया जाता है।

समस्या–4 अध्यापकों के लिए शैक्षिक–भ्रमण की सुविधा न मिलने की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रदर्शित की है। स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अपेक्षा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को शैक्षिक–भ्रमण की सुविधा कम प्रदान की जाती है।

समस्या–5 समय–समय पर शैक्षिक–संगोष्ठी का आयोजन न होने के कारण शैक्षिक–नवाचारों से अवगत न होने की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः इस समस्या का प्रतिशत भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक है, जहाँ पर शैक्षिक नवाचारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

समस्या–6 अध्यापकों के लिए शैक्षिक–अद्यतन सामग्री का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 92.72 प्रतिशत

अध्यापकों ने इस समस्या को प्रभावी समस्या बताया है।

समस्या–7 विद्यालयों में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से विषयानुगत प्रवक्ताओं की नियुक्ति का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय; सत्र के दौरान अध्यापकों की विषयागत नियुक्तियाँ नहीं करते हैं।

समस्या–8 विद्यालयों में शैक्षिक–नेतृत्व एवं शैक्षिक–पर्यावरण का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.81 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–9 वर्तमान पाठ्यक्रम का आधुनिक जीवन के उद्देश्यों के अनुकूल न होना।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 89.09 प्रतिशत अध्यापकों ने इस समस्या पर सहमति प्रकट की है। अतः यह समस्या वर्तमान जगत की एक प्रमुख शैक्षिक समस्या है।

समस्या–10 शैक्षिक स्वतन्त्रता के अभाव में स्तरानुकूल–शिक्षण में कठिनाई की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 72.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 92.72 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या है।

समस्या–11 पुस्तकालयों में स्तरीय–सुविधाओं का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 45 प्रतिशत अध्यापकों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी समस्या है।

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भौतिक–संसाधनों से सम्बन्धित समस्याओं से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रतिशत को अग्र तालिका संख्या–3 द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका संख्या–3

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भौतिक–संसाधनों से संबन्धित समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	विद्यालयों में पयाप्त कक्षा–कक्षों का न होना।	10	12.50	150	68.18	160	53.33
2	विद्यालयों में अपेक्षित एवं वांछनीय सुविधाओं का अभाव।	12	15.00	180	81.82	192	64.00
3	विद्यालयों में पीने के पानी एवं कैंटीन की पर्याप्त सुविधा का अभाव।	70	87.50	190	86.36	260	86.66
4	विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, छात्रानुपात के अनुसार न होना।	10	12.50	200	90.90	210	70.00
5	विद्यालयों में पुस्तकालय–सुविधा का स्तरीय व पर्याप्त न होने से सन्दर्भ पुस्तकों के ज्ञान का अभाव।	50	62.50	160	72.73	210	70.00
6	व्यावहारिक एवं प्रायोगिक–कार्य कौशलों के विकास के लिए पर्याप्त साधन–सामग्री उपलब्ध न होना।	48	60.00	200	90.90	248	82.66
7	विद्यालयों में प्राथमिक–चिकित्सा सुविधा का अभाव।	70	87.50	210	95.45	280	93.33
8	रिक्त–कालांशों में अध्यापकों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था न होना।	76	95.00	214	97.27	290	96.66
9	प्रयोगशाला व प्रयोगात्मक–सामग्री का अभाव।	50	62.50	180	81.82	230	76.66
10	विद्यालयों में खेल के लिए पर्याप्त मैदान का अभाव।	30	37.50	160	72.73	190	63.33
	माध्य प्रतिशत		53.25		83.81		75.66

तालिका संख्या–3 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–2 पर 15 प्रतिशत, समस्या–3 पर 87.50 प्रतिशत, समस्या–4 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–5 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–6 पर 60 प्रतिशत, समस्या–7 पर 87.50 प्रतिशत, समस्या–8 पर 95 प्रतिशत, समस्या–9 पर 62.50 प्रतिशत, तथा समस्या–10 पर 37.50 प्रतिशत, सहमति व्यक्त की है। वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 68.18 प्रतिशत, समस्या–2 पर 81.82 प्रतिशत, समस्या–3 पर 86.36 प्रतिशत, समस्या–4 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–5 पर 72.73 प्रतिशत, समस्या–6 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–7 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–8 पर 97.27 प्रतिशत, समस्या–9 पर 81.82 प्रतिशत, तथा समस्या 10 पर 72.73 प्रतिशत, सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि इन समस्याओं का प्रतिशत भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक है।

शोधकर्ता ने प्रत्येक भौतिक–संसाधन से सम्बन्धित समस्या की प्रतिशत के आधार पर गणना की है। यह निम्न प्रकार है–

समस्या–1 विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा–कक्षों का न होना।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 68.18 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–2 विद्यालयों में अपेक्षित एवं वांछनीय सुविधाओं का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 15 प्रतिशत अध्यापकों ने तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.82 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–3 विद्यालयों में पीने के पानी तथा कैंटीन की पर्याप्त सुविधा का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 86.36 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है।

समस्या–4 विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या; छात्र–अनुपात के अनुसार न होना।
उक्त समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या है, जिससे अध्यापकों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
समस्या–5 विद्यालयों में पुस्तकालय–सुविधा का स्तरीय व पर्याप्त न होने से सदंर्भ–पुस्तकों के ज्ञान का अभाव।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 72.73 प्रतिशत अध्यापकों ने इंगित किया है। अतः यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या है तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की कम प्रभावी समस्या है।
समस्या–6 व्यावहारिक एवं प्रायोगिक कार्य–कौशलों के विकास के लिए पर्याप्त साधन–सामग्री उपलब्ध न होने की समस्या।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 60 प्रतिशत अध्यापकों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम प्रभावी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है।
समस्या–7 विद्यालयों में प्राथमिक–चिकित्सा सुविधा का अभाव।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः यह समस्या लगभग दोनों ही विद्यालयों की समान समस्या स्पष्ट प्रतीत होती है। इन विद्यालयों में प्राथमिक–चिकित्सा सुविधा की कोई सुविधा नहीं होती है।
समस्या–8 रिक्त–कालांशों में अध्यापकों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था न होना।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 95 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 97.27 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः यह समस्या भी दोनों की प्रभावी समस्या है, किन्तु यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक दिखायी पड़ी है, जहाँ पर रिक्त–कांलाशों में बैठने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होती है।
समस्या–9 प्रयोगशाला व प्रयोगात्मक–सामग्री का अभाव।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.82 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक उपकरणों का अभाव पाया जाता है, किन्तु यह अभाव की मात्रा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिक प्रभावी है।
समस्या–10 विद्यालयों में खेल के लिए पर्याप्त मैदान का अभाव।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 37.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 72.72 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि औसत रूप से यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या है।
उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की वित्तीय समस्याओं से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रतिशत संगणन को तालिका संख्या–4 में दर्शाया गया है–

तालिका संख्या–4

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की वित्तीय–समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अध्यापकों को छात्रों के शैक्षिक–भ्रमण आदि के दौरान यात्रा भत्ता व भोजन भत्ता न मिलना।	60	75.00	160	72.72	220	73.33
2	अध्यपकों को नियत वेतनमान का अभाव।	04	05.00	200	90.90	204	68.00
3	शैक्षिक–संगोष्ठी, कार्याशालाओं आदि में सहभागिता हेतु सवेतन–अवकाश व आर्थिक सहायता का अभाव।	50	62.50	210	95.45	260	86.66
4	प्रबंध–तंत्र का अध्यापकों एवं छात्रों के प्रति वांछित शैक्षिक–दृष्टिकोण का अभाव।	20	25.00	180	81.81	200	66.66
5	विद्यालयों में (जहाँ पर आप कार्यरत हैं) वित्तीय सहायता न मिलने की समस्या।	70	87.50	220	100	290	96.66
6	माह की अन्तिम तारीख को वेतन न मिलना।	20	25.00	220	100	240	80.00
7	निजी–लेखन, प्रकाशन व ट्यूशन का अभाव।	16	20.00	210	95.45	226	75.33
8	अध्यापकों को जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./ग्रेच्युटी आदि न मिलना।	12	15.00	216	98.18	228	76.00
9	सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ न मिलना।	00	00	212	96.36	212	70.66
10	ग्रीष्म–अवकाश का वेतन न मिलने की समस्या।	00	00	200	90.90	200	66.66
	माध्य प्रतिशत		31.50		92.18		76.00

तालिका संख्या–4.04 को देखने से ज्ञात होता है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 75 प्रतिशत, समस्या–2 पर 5 प्रतिशत, समस्या–3 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–4 पर 25 प्रतिशत, समस्या–5 पर 87.50 प्रतिशत, समस्या–6 पर 25 प्रतिशत, समस्या–7 पर 20 प्रतिशत तथा समस्या–8 पर 15 प्रतिशत, सहमति व्यक्त की है। समस्या–9 व 10 पर कोई सहमति व्यक्त नहीं की है।
वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 72.72 प्रतिशत, समस्या–2 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–3 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–4 पर 81.81 प्रतिशत, समस्या–5 पर 100 प्रतिशत, समस्या–6 पर 100 प्रतिशत, समस्या–7 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–8 पर 98.18 प्रतिशत, समस्या–9 पर 96.36 प्रतिशत, एवं समस्या–10 पर 90.90 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है।
शोधकर्ता ने प्रत्येक वित्तीय–समस्या की प्रतिशत के आधार पर विवेचना की है, जो निम्न प्रकार हैः–

समस्या–1 अध्यापकों को छात्रों के शैक्षिक–भ्रमण के दौरान; यात्रा–भत्ता व भोजन–भत्ता न मिलना।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 72.72 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः औसत रूप से यह समस्या राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है, जहाँ पर छात्रों के शैक्षिक–भ्रमण के दौरान भोजन–भत्ता व यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाता है।
समस्या–2 अध्यापकों को नियत वेतनमान के अभाव की समस्या।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 5 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत विद्यालयों के अध्यापकों ने बताया है। अतः स्पष्ट है कि यह वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है, जहाँ पर नियत वेतनमान नहीं दिया जाता है।
समस्या–3 शैक्षिक–संगोष्ठी, कार्यशालाओं आदि में सहभागिता हेतु सवेतन–अवकाश व आर्थिक सहायता का अभाव।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की एक प्रभावी समस्या है, जहाँ पर शैक्षिक–संगोष्ठी/कार्यशालाओं में सहभागिता हेतु आर्थिक– खर्च एवं सवेतन–अवकाश नहीं दिया जाता है।
समस्या–4 प्रबन्ध–तंत्र का अध्यापकों एवं छात्रों के प्रति वांछित शैक्षिक– दृष्टिकोण का अभाव।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.81 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः यह समस्या औसत रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है, जहाँ पर शैक्षिक–दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है।
समस्या–5 विद्यालयों में (जहाँ पर आप कार्यरत हैं) वित्तीय–सहायता न मिलने की समस्या।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः यह समस्या औसत रूप से दोनों विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है, किन्तु वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है, जहाँ पर वित्तीय सहायता का नितांत अभाव पाया जाता है।
समस्या–6 माह की अन्तिम तारीख को वेतन न मिलने की समस्या।
इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रभावी समस्या बताया है, जहाँ पर माह की अन्तिम तारीख को वेतन नहीं दिया जाता है।
समस्या–7 निजी लेखन, प्रकाशन व ट्यूशन के अभाव की समस्या।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 20 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या औसत रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की एक प्रभावी समस्या है।
समस्या–8 अध्यापकों को जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ०/ग्रेच्यूटी आदि न मिलने की समस्या।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 15 प्रतिशत अध्यापकों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 98.18 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक प्रभावी समस्या है, क्योंकि वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अधिकांशतः इस प्रावधान का अभाव पाया जाता है।
समस्या–9 सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ न मिलना।
इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं की है, क्योंकि इन विद्यालयों में स्वतः ही सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 96.36 प्रतिशत अध्यापकों ने इस समस्या पर सहमति व्यक्ति की है। अतः स्पष्ट है कि इन विद्यालयों के अध्यापकों को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती है।
समस्या–10 ग्रीष्म–अवकाश का वेतन न मिलने की समस्या।
इस समस्या पर भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने कोई सहमति व्यक्त नहीं की है एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने इसे प्रभावी समस्या के रूप में व्यक्त किया है। यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की एक प्रभावी समस्या है, जहाँ पर ग्रीष्म–अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की व्यावसायिक समस्याओं से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रतिशत को तालिका संख्या–5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–5

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की व्यावसायिक समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	पदोन्नति के समानावसर न मिलने की समस्या।	10	12.50	216	98.18	226	75.33
2	अध्यपकों में व्यावसायिक–सुरक्षा का भय।	10	12.50	220	100	230	76.66
3	समय पर नियत वेतन–वृद्धि का अभाव।	20	25.00	200	90.90	220	73.33
4	विद्यालय में सरकार के मानकानुसार गुणवत्तापरक् शिक्षण–कार्य नहीं कराते हैं।	10	12.50	212	96.36	222	74.00
5	अवकाश का सदुपयोग नहीं किया जाता है।	08	10.00	214	97.27	222	74.00
6	अधिक कार्य करने से अध्यापकों में मानसिक तनाव की समस्या।	20	25.00	208	94.54	228	76.00
7	वृत्तिक–उन्नयन के अवसरों के अभाव में अध्यापकों की व्यावसायिक–दक्षता पर नकरात्मक प्रभाव।	50	62.50	220	100	270	90.00
8	व्यावसायिक–उन्नयन की दृष्टि से अध्यापकों में परस्पर सामंजस्य का अभाव।	40	50.00	200	90.90	240	80.00

9	शिक्षण–व्यवसाय का वर्तमान समाज में सम्मानीय न होना।	70	87.50	180	81.82	250	83.33
10	शिक्षण–व्यवसाय के प्रति रूचि न होने के कारण वांछनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने में असमर्थता।	60	75.00	200	90.90	260	86.66
	माध्य प्रतिशत		37.25		94.09		78.93

तालिका संख्या–5 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–2 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–3 पर 25 प्रतिशत, समस्या–4 पर 12.50 प्रतिशत, समस्या–5 पर 10 प्रतिशत, समस्या–6 पर 25 प्रतिशत, समस्या–7 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–8 पर 50 प्रतिशत, समस्या–9 पर 87.50 प्रतिशत, तथा समस्या–10 पर 75 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है। वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 98.18 प्रतिशत, समस्या–2 पर 100 प्रतिशत, समस्या–3 पर 90.90 प्रतिशत , समस्या–4 पर 96.36 प्रतिशत, समस्या–5 पर 97.27 प्रतिशत, समस्या–6 पर 94.54 प्रतिशत, समस्या–7 पर 100 प्रतिशत, समस्या–8 पर 90.90 प्रतिशत, समस्या–9 पर 81.82 प्रतिशत तथा समस्या–10 पर 90.90 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है।

शोधकर्ता ने प्रत्येक व्यावसायिक–समस्या की प्रतिशत के आधार पर विवेचना की है, जो निम्नलिखित है–

समस्या–1 पदोन्नति के समान अवसर न मिलने की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 98.18 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि औसत रूप से यह समस्या; वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है, क्योंकि इन संस्थानों में पदोन्नति का कोई मानक नहीं होता है।

समस्या–2 अध्यापकों में व्यावसायिक–सुरक्षा का भय।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने अभिव्यक्त किया है। अतः इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक–सुरक्षा की समस्या; वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–3 समय पर नियत वेतन–वृद्धि का अभाव।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने इस समस्या को प्रभावी समस्या बताया है, क्योंकि अधिकांश वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समय पर नियत–वेतनवृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होता है।

समस्या–4 विद्यालय; सरकार के मानक के अनुसार गुणवत्तापरक् शिक्षण–कार्य नहीं कराते हैं।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 96.36 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः औसत रूप से यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रभावी समस्या है, जहाँ पर शिक्षण में सरकार के मानकों का पालन नहीं किया जाता है।

समस्या–5 अवकाश का सदुपयोग नहीं किया जाता है।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 10 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 97.27 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है, जहाँ पर अवकाश का सदुपयोग नहीं किया जाता है।

समस्या–6 अधिक कार्य करने से अध्यापकों में मानसिक तनाव की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 94.54 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः औसत रूप से यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है।

समस्या–7 वृत्तिक–उन्नयन के अवसरों के अभाव में अध्यापकों की व्यावसायिक–दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 100 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या भी औसत रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्या है, जहाँ पर वृत्तिक–उन्नयन के अवसरों का सदुपयोग नहीं करने दिया जाता है।

समस्या–8 व्यावसायिक–उन्नयन की दृष्टि से अध्यापकों में परस्पर– सांमजस्य का अभाव।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रभावी समस्या बताया है।

समस्या–9 शिक्षण–व्यवसाय का आधुनिक समाज में सम्माननीय न होने की समस्या।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.82 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रभावी समस्या बताया है।

समस्या–10 शिक्षण–व्यवसाय के प्रति रूचि न होने के कारण वांछनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने में असमर्थता।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 90.90 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रभावी समस्या बताया है।

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रतिशत को तालिका संख्या–6 में व्यक्त किया गया है–

तालिका संख्या–6

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अनुशासन–सम्बन्धी समस्याओं पर प्राप्त सहमति का विश्लेषण

क्र. सं.	क्रमांकानुसार समस्याएँ	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=80		वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक N=220		कुल योग N=300	
		सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	सहमति देने वाले अध्यापक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अध्यापकों की आपसी–गुटबंदी की समस्या।	20	25.00	210	95.45	230	76.66
2	विद्यालयों में छात्र–संघों के चुनाव की समस्या।	70	87.50	00	00	70	23.33
3	सह–शिक्षा के कारण अनुशासन की समस्या।	50	62.50	130	59.09	180	60.00

4	पाठ्य–सहगामी क्रियाओं के अभाव की समस्या।	10	12.50	160	72.72	170	56.66
5	पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था का अभाव।	20	25.00	180	81.81	200	66.66
	माध्य प्रतिशत		42.50		61.81		56.66

तालिका संख्या–6 से स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 25 प्रतिशत, समस्या–2 पर 87.50 प्रतिशत, समस्या–3 पर 62.50 प्रतिशत, समस्या–4 पर 12.50 प्रतिशत तथा समस्या–5 पर 25 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है।

वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने समस्या–1 पर 95.45 प्रतिशत, समस्या–2 पर कोई सहमति व्यक्त नहीं की है, समस्या–3 पर 59.09 प्रतिशत, समस्या–4 पर 72.72 प्रतिशत तथा समस्या–5 पर 81.81 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है।

शोधकर्ता ने प्रत्येक अनुशासन सम्बन्धी समस्या की विवेचना प्रतिशत के आधार पर की है, जो निम्नवत् है–

समस्या–1 अध्यापकों की आपसी–गुटबंदी की समस्या।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 95.45 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः स्पष्ट है कि यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–2 विद्यालयों में छात्रसंघों के चुनाव की समस्या।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 87.50 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की तथा वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने कोई सहमति व्यक्त नहीं की है क्योंकि वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–संघों के चुनाव नहीं होते हैं। अतः इन विद्यालयों में छात्र–संघों के चुनाव की समस्या नहीं होती है।

समस्या–3 सह–शिक्षा के कारण अनुशासन की समस्या।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 62.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 59.09 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया है। अतः यह समस्या राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की एक समान प्रभावी समस्या है।

समस्या–4 पाठ्यक्रम–सहगामी क्रियाओं के अभाव की समस्या।

इस समस्या को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12.50 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 72.72 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रभावी समस्या बताया है। अतः यह समस्या वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अधिक प्रभावी समस्या है।

समस्या–5 पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था का अभाव।

इस समस्या पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 25 प्रतिशत अध्यापकों ने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 81.81 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की है। अतः यह समस्या भी वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रभावी समस्या है, जहाँ पर पुस्तकालयों में समुचित स्थान का अभाव होता है।

शोध परिकल्पना संख्या–1 "उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्याएँ भिन्न–भिन्न होगी" के सत्यापन की पूर्ति हेतु आँकड़ों का विश्लेषण; तालिका सं०–1 में प्रशासनिक, तालिका–2 में शैक्षिक, तालिका–3 में भौतिक संसाधनों से सम्बन्धित, तालिका–4 में वित्तीय, तालिका–5 में व्यावसायिक, एवं तालिका–6 में अनुशासन में विविध समस्याओं का प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

उपरोक्त तालिकाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रभावी समस्याएँ भिन्न–भिन्न हैं। तुलनात्मक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सभी क्षेत्रों की समस्याएँ अधिक प्रभावी है तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कम प्रभावी समस्याएँ हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रथम शोध परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

सन्दर्भः

1. अग्रवाल, सुभाष चन्द एवं दीक्षित पवन, शंकर (2005). 'अध्यापक प्रशिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन' प्राइमरी शिक्षक, नई दिल्लीः एन०सी०ई०आर०टी०, अंक जनवरी, 2005।
2. अरोरा, कमला (1976) 'ए स्टडी ऑफ करेक्टरस्टिक डिफरेंस बिटविन इफेक्टिव एण्ड इनइफेक्टिव टीचर्स ऑफ हायर सेकेण्डरी स्कूल्स' ए क्वार्टरली जर्नल ऑफ इंडियन डिजरटेशन एस्टैक्ट, जनवरी–मार्च 1976, वोल्यूम 4, नं० 1, पृ०सं०–27।
3. कौल, लोकेश (2007) 'शैक्षिक अनुसंधान की कार्य–प्रणाली', नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।
4. कौशिक, विवेक (2006). 'स्व वित्तपोषित शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की समस्याएँ–एक अध्ययन', भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्ली, एन०सी०ई०आर०टी०, अंक–4, अप्रैल–1।
5. चौधरी, प्यारे लाल (2006) भावी शिक्षक एवं शिक्षा तकनीकी, जयपुर, स्वाती पलिकेशन।
6. बिहारी, रमन लाल (2004) 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, मेरठ, रस्तौगी प्रकाशन।
7. भार्गव, महेश (2005) 'आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण व मापन' आगरा, एच०पी० बुक हाउस।
8. वासवा, एन०पी० (1991) 'गुजरात राज्य में उच्च शिक्षा की प्रगति और समस्याएँ', पी–एच०डी०, गुजरात विश्वविद्यालय।